



धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा दो!

संवाददाता

देहरादून। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग व छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने सचिवालय कूच किया। जिनको बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस द्वारा रोक दिया गया।

आज यहां विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। जहां से

छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विभिन्न संगठनों ने किया सचिवालय कूच, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से की इस्तीफे की मांग

उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। जब वह सचिवालय के पास पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया जिसके बाद वह वहीं पर धरने पर बैठ गये। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि गत दिवस दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन पर गैस के गोले दागे।

उनका कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता



होनी चाहिए। बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया जिससे उनको काफी निराशा हाथ लगती है। उनका कहना है कि सरकार खोखले दावे करती है कि उन्होंने इतने हजार लोगों को रोजगार दिया है

लेकिन सरकार पेपर लीक मामले में नाकाम साबित हो रही है। बच्चे पेपर की तैयारियां करते हैं लेकिन उनकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रहता और सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है।

कई बार लोक सेवा आयोग से भी मांग की गयी कि वह भर्ती का विज्ञापन जारी करें लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा।

मंदिर के पास मिट्टी में दबे मिले दो साधुओं के शव

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित पथरेश्वर महादेव मंदिर परिसर के समीप दो साधुओं के बीती देर रात शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोनों शव जंगल क्षेत्र में मिट्टी

◆हत्या की आशंका, जांच शुरू-कई हिरासत में

के नीचे दबे मिले, सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाई शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को मंदिर से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पुलिस की जांच के दायरे में मंदिर के मुख्य पुजारी सहित कुछ अन्य लोग भी हैं। हालांकि पुलिस



अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी और सभी संभावित पहलुओं को

ध्यान में रखकर निष्पक्ष एवं गहन जांच की जा रही है। पुलिस की कई टीमों संभावित संदिग्धों की तलाश में लगातार

दबिश दे रही हैं। घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र से मिले साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट तथा अन्य तकनीकी तथ्यों के आधार पर

पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा सके।

दोहरे शव मिलने की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास जुटे रहे। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद मौत के कारणों और घटना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद है।

दून वैली मेल

संपादकीय

संसद के दरवाजे तक जेन-जेड

सालों बाद देश ने एक ऐसा दृश्य देखा, जिसने सत्ता के गलियारों को यह एहसास करा दिया कि युवा केवल चुनावी रैली की भीड़ नहीं होता, वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। संसद के बाहर उमड़ा जेन-जेड का आक्रोश इस बात का संकेत है कि देश की नई पीढ़ी अब केवल लाइक, शेयर और हैशटैग तक सीमित नहीं रहना चाहती। जब उसे अपने भविष्य पर संकट दिखाई देता है, तो वह संसद की चौखट तक पहुंचने का साहस भी रखती है। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं था। यह उन लाखों युवाओं की हताशा, बेचौनी और टूटते भरोसे की आवाज थी, जो वर्षों से रोजगार, भर्ती परीक्षाओं, पारदर्शिता और अवसरों के नाम पर केवल आश्वासन सुनते आए हैं। देश की राजनीति ने लंबे समय तक युवाओं को केवल वोट बैंक समझा। चुनाव आते ही रोजगार के वादे, स्टार्टअप के सपने, कौशल विकास के विज्ञापन और डिजिटल इंडिया के नारे गुंजते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही युवा फाइलों, अदालतों, भर्ती घोटालों और लंबी प्रतीक्षा सूचियों में उलझ जाता है। जब उम्मीद बार-बार टूटती है, तो गुस्सा सड़कों पर उतरता है और जब वह गुस्सा संसद के बाहर पहुंच जाए, तो समझ लेना चाहिए कि समस्या अब राजनीतिक नहीं, सामाजिक विस्फोट का रूप लेने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या सरकारें युवाओं की आवाज समय रहते सुनने में विफल रहीं? क्या विपक्ष केवल ट्वीट और प्रेस कान्फ्रेंस तक सीमित रहा? यदि लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता की बेचौनी को समय रहते नहीं सुनतीं, तो सड़कें ही संवाद का मंच बन जाती हैं। यह विडंबना ही है कि जिस जेन-जेड को अक्सर रील्स वाली पीढ़ी, संवेदनहीन पीढ़ी या राजनीति से दूर पीढ़ी कहकर खारिज किया जाता था, वही आज सबसे मुखर होकर सवाल पूछ रही है। यह पीढ़ी नेताओं के भाषणों से नहीं, उनके प्रदर्शन से फैंसले करती है। इसे आंकड़ें चाहिए, जवाब चाहिए और परिणाम चाहिए। सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं होता, बल्कि निराश युवा होता है। क्योंकि विपक्ष चुनाव में हराया जा सकता है, लेकिन उम्मीद खो चुका युवा किसी भी सरकार के लिए सबसे कठिन चुनौती बन जाता है। इतिहास गवाह है कि जब-जब युवाओं का असंतोष चरम पर पहुंचा है, तब-तब राजनीति की दिशा बदल गई है। यह भी सच है कि विरोध लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन विरोध का लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहना भी उतना ही आवश्यक है। हिंसा, टकराव और अराजकता किसी भी आंदोलन की नैतिक शक्ति को कमजोर करते हैं। दूसरी ओर, यदि शांतिपूर्ण विरोध का जवाब केवल बैरिकेड, लाठी या हिरासत से दिया जाता है, तो सत्ता अपनी नैतिक बढ़त स्वयं खो देती है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आईना देखने की जरूरत है। सत्ता को यह समझना होगा कि रोजगार केवल चुनावी घोषणा नहीं, युवाओं का संवैधानिक विश्वास है। विपक्ष को भी यह तय करना होगा कि वह युवाओं की पीड़ा को केवल राजनीतिक अवसर नहीं बनाए, बल्कि ठोस विकल्प भी दे। संसद के बाहर पहुंचे जेन-जेड ने दरअसल संसद के भीतर बैठे हर दल से एक ही सवाल पूछा है हमारे भविष्य का जवाब कौन देगा? इस सवाल का उत्तर यदि केवल भाषणों, आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक शोर में दब गया, तो आने वाले समय में यह दस्तक और तेज होगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि युवा सड़क पर उतर आया। सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि संसद उसकी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दे। क्योंकि जब उम्मीदें बैरिकेड से टकराने लगती हैं, तब केवल आंदोलन नहीं जन्म लेते इतिहास भी करवट लेता है।

एक सप्ताह में आधार सीडिंग-डीबीटी पूरी करें, वरना होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी

संवाददाता

रुद्रप्रयाग। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने निर्देश दिये कि एक सप्ताह में आधार सीडिंग-डीबीटी पूरी करें वरना कार्रवाई की जायेगी।

आज यहां जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जनपद के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक बैंक खाते आधार से लिंक न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों का डाटा तत्काल दुरुस्त किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत जनपद में कुल 498 छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हैं। इनमें विकासखंड अगस्त्यमुनि के 232, जखोली के 194 और विकासखंड ऊखीमठ के 72 लाभार्थी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिन छात्र-छात्राओं का किसी कारण से आधार सीडिंग संभव नहीं है, उनका वास्तविक विवरण शीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। पूर्व में भी शत-प्रतिशत आधार सीडिंग के निर्देश दिए जा चुके हैं। निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि इसमें लापरवाही बरतने पर संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पात्र छात्र-छात्राएं योजना के लाभ से वंचित न रहें, इसके लिए सभी संस्थान प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।



जेन जेड की 'आवाज' पर राष्ट्रीय बहस

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन अब केवल छात्रों का प्रदर्शन नहीं रह गया है। सोशल मीडिया की ताकत ने इसे राष्ट्रीय बहस में बदल दिया है। विपक्षी नेताओं, फिल्मी हस्तियों और छात्र संगठनों के खुलकर सामने आने से केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। वहीं सरकार और पुलिस अपने कदमों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बता रही है। प्रदर्शन के दौरान सामने आए वीडियो और तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आंदोलन से जुड़े हैशटैग लगातार ट्रेंड करते रहे। हजारों लोग छात्रों के समर्थन में पोस्ट साझा करते दिखे, जबकि सत्ता पक्ष के समर्थकों ने पुलिस कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुना जाना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार संवाद की जगह दमन का रास्ता अपना रही है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को संसद के भीतर और बाहर उठाने के संकेत दिए हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं, फिल्म जगत की कई चर्चित हस्तियां भी छात्रों के समर्थन में सामने आईं। अभिनेता सोनू सूद ने कहा



कि छात्रों को लाठियां नहीं, गले लगाने वाले हाथ चाहिए। अभिनेता रितेश देशमुख ने लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का समर्थन किया। वरिष्ठ अभिनेत्री शबाना

◆जंतर-मंतर से युवाओं की हुंकार से सोशल मीडिया पर गुंजा देश
◆राहुल गांधी से लेकर बालीवुड सितारे तक जेन जेड के समर्थन में
◆सरकार पर दबाव, पुलिस बोली-कानून-व्यवस्था थी प्राथमिकता

आजमी ने असहमति के सम्मान की बात कही, जबकि अभिनेता प्रकाश राज ने सरकार से छात्रों के साथ संवाद स्थापित करने की अपील की। इन प्रतिक्रियाओं के बाद आंदोलन को सोशल मीडिया पर और अधिक गति मिली।

विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन इसलिए भी अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत सोशल

मीडिया बन गया है। प्रदर्शन स्थल से लाइव वीडियो, पुलिस कार्रवाई के दृश्य और छात्रों के बयान कुछ ही मिनटों में देशभर में पहुंच गए। कई विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों ने भी आनलाइन समर्थन अभियान शुरू कर दिया है।

हालांकि सरकार और दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग पार करने और प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया था। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई नियमानुसार की गई और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी प्रदर्शन

►► शेष पृष्ठ 7 पर

उत्तराखंड में 'इलेक्शन मोड' ऑन

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की औपचारिक घोषणा भले अभी दूर हो, लेकिन राज्य की राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। एक ओर भाजपा लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस संगठन को पुनर्जीवित करने, बूथ स्तर तक पहुंच बनाने और स्थानीय मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, मजबूत संगठन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए गए कार्य उसे फिर सत्ता तक पहुंचाएंगे। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, पेपर लीक, स्वास्थ्य और पहाड़ों से जुड़े बुनियादी सवालों पर सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड में भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी उसका बूथ नेटवर्क और संगठनात्मक ढांचा है। पार्टी लंबे समय से बूथ प्रबंधन, लाभार्थी संपर्क और कार्यकर्ता-आधारित चुनावी माडल पर काम करती रही है। चुनाव से पहले भी संगठन को गांव-गांव और घर-घर तक सक्रिय करने की कवायद तेज है। भाजपा का आकलन है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उसे चुनावी बढ़त दिला सकता है। सत्ता में लगातार दो कार्यकाल पूरे करने के बाद किसी भी



□भाजपा हैट्रिक की तैयारी में और कांग्रेस ने रत्ती सत्ता की तूह रचना
□भाजपा का विकास कार्ड पर कांग्रेस का पलायन व रोजगार पर वार
□चुनाव में स्थानीय मुद्दों की कसौटी पर होगी सत्ता की असली परीक्षा

सरकार के सामने स्वाभाविक रूप से स्थानीय असंतोष की चुनौती आती है। कई क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दे अभी भी प्रमुख चुनावी विषय बने हुए हैं।

इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ स्थानीय नाराजगी की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती हैं। ऐसे में भाजपा के लिए उम्मीदवार चयन भी एक अहम चुनौती हो सकता है।

कांग्रेस इस बार केवल सरकार विरोधी राजनीति तक सीमित रहने के बजाय बूथ संगठन, मेनिफेस्टो और जनसंपर्क पर विशेष जोर देती दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक एकजुटता और चुनावी तैयारी पर विशेष बल दिया है। यदि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर पाती है, तो कई सीटों पर मुकाबला पहले से अधिक

कड़ा हो सकता है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार इन मुद्दों की भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। युवाओं के लिए रोजगार और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, पलायन और पर्वतीय क्षेत्रों का विकास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं, पर्यटन, चारधाम और स्थानीय अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा और स्वरोजगार, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, महंगाई और किसान हित प्रमुख हैं। भाजपा की रणनीति विकास, संगठन और नेतृत्व पर केंद्रित रहने की संभावना है, जबकि कांग्रेस स्थानीय असंतोष, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों और संगठन विस्तार के जरिए चुनावी बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। क्षेत्रीय दल भी कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं।

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 2027 का चुनाव केवल नारों का नहीं, बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट बनाम जनभावनाओं की लड़ाई होगा। भाजपा का लक्ष्य अपने मजबूत संगठन को वोट में बदलना होगा, जबकि कांग्रेस के सामने चुनौती यह होगी कि वह सरकार विरोधी रुझानों को प्रभावी चुनावी समर्थन में बदल पाए। यानी कि प्रचंड बहुमत का दावा और सत्ता परिवर्तन की उम्मीद दोनों की असली परीक्षा अब चुनावी मैदान में होगी। उत्तराखंड की राजनीति का अगला अध्याय बूथों पर लिखा जाएगा, जहां अंतिम फैसला मतदाता करेगा।

भारकोटबार भंगोटा में नंदादेवी मंदिर के कपाट खुले

नंदाधाम भारकोटबार भंगोटा में नंदादेवी मंदिर के कपाट खुले। भूमियाल देवता के आगमन और नंदादेवी मंदिर के कपाटोद्घाटन के साथ चार दिवसीय नंदा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मध्य कड़ाकोट पट्टी के नौ गांवों के सहयोग से हर तीसरे वर्ष यह महोत्सव आयोजित होता है। सुबह खेन्टीखाल में आचार्यों ने चनौणा पूजन किया। इसके बाद ग्रामीण बाजे-गाजे के साथ भूमियाल देवता को लेने रैंस गांव पहुंचे। रैंस गांव में भूमियाल देवता की मूर्ति निशाण पर स्थापित कर पूजा-अर्चना की गई। भूमियाल देवता के निशाण ने शंखनाद के साथ नंदाधाम भारकोटबार के लिए प्रस्थान किया। भारकोटबार में आचार्यों ने सरकोल पूजन कर भूमियाल देवता का आह्वान किया। भूमियाल देवता के पश्चा ने मां नंदादेवी मंदिर के कपाट खोले। नंदा भक्तों ने जयकारे लगाए और अक्षत व पुष्प बरसाए। मंदिर के कपाटोद्घाटन पर पुजारी राजेंद्र प्रसाद सती और भास्करानंद सती ने गणेश व पंचांग पूजा की। जागर सम्राट बुद्धि सिंह दानू ने मां नंदा के जागर गाए। अगले चार दिनों तक नंदाधाम भारकोटबार में मां नंदा के जागर गूंजते रहेंगे। सोमवार को भूमियाल देवता की अगुवाई में मां गिरिजा भवानी के दर्शन होंगे। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, मां नंदा के श्रृंगार दर्शन और देवी अवतरण के जागर गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस अवसर पर मेला समिति के अध्यक्ष जयवीर सिंह रावत, मंदिर समिति के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह मेहरा, कनिष्ठ उपप्रमुख भूपेंद्र सिंह मेहरा, सतेंद्र मेहरा, प्रधान मीना देवी, कुशवर मेहरा समेत बड़ी संख्या में नंदाभक्त मौजूद रहे।

छह गांव के लोगों पर भारी पड़ रही लोनिवि की लापरवाही

नई टिहरी(आरएनएस)। लोनिवि की लापरवाही भिलंगना ब्लॉक के घोंटी, गोजियाणा, सांगिड्या, बणचुरी, इंदोला, दोणी, सांझघेरा गांव के लोगों पर भारी पड़ रही है। उक्त गांवों को यातायात से जोड़ने वाला करीब 11 किमी लंबा घोंटी- इंदोला-सांझघेरा मोटर मार्ग बदहाल हो चुका है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। डामर पूरी तरह उखड़ चुका है। ऐसे में लोगों को हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। घोंटी- इंदोला-सांझघेरा सड़क का निर्माण 2००8 में किया गया था। 2०12 में सड़क मार्ग पर डामरीकरण किया गया था जो कुछ समय बाद ही उखड़ना शुरू हो गया था। इसके बाद मार्ग का डामरीकरण नहीं कराया गया। समय पर मरम्मत कार्य नहीं होने से सड़क की हालत लगातार बिगड़ती गई। क्षेत्र की करीब पांच हजार की आबादी के लिए मार्ग मुख्य संपर्क सड़क है। स्कूल, बाजार, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग प्रतिदिन इसी सड़क का उपयोग करते हैं। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। बीडीसी सदस्य ममता देवी, ग्राम प्रधान कमला देवी, सुरजा देवी, भगवान दास, रविंद्र नेगी, हुकम सिंह, बाग सिंह, शिव सिंह का कहना है कि कई बार लोनिवि के अधिकारियों से सड़क के डामरीकरण और मरम्मत की मांग की गई लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। समस्या को देखते हुए शीघ्र ही सड़क पर मरम्मत और डामरीकरण कार्य शुरू किया जाना चाहिए। यह सड़क पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन थी। हाल ही में लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हुई है। सड़क के डामरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। फिलहाल गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है।

विधायक ने मांगा एक माह का समय, ग्रामीण आंदोलन पर अड़े

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। तल्ला नागपुर क्षेत्र की लंबित चार सूत्री मांगों के लिए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। क्षेत्र के विकास को लेकर शासन-प्रशासन के ढुलमुल रवैये से नाराज ग्रामीणों को मनाने के लिए केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी पहुंचीं। उन्होंने एक माह का समय मांगा लेकिन ग्रामीण नहीं माने। जनप्रतिनिधियों ने साफ कहा कि तल्ला नागपुर को अब तक केवल झूठे आश्वासन देकर छला गया है। इसलिए जब तक धरातल पर काम शुरू नहीं होता तब तक 22 जुलाई से प्रस्तावित क्षेत्रीय आंदोलन को किसी भी हाल में स्थगित नहीं किया जाएगा।ग्रामीण क्षेत्र में पॉलिटेक्निक भवन निर्माण, पेयजल व पार्किंग निर्माण आदि की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में गत माह स्थानीय लोगों की बैठक हुई थी जिसमें प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। इसी सिलसिले में केदारनाथ विधायक ने चोपता में जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के साथ वार्ता की। इस दौरान अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर लोगों ने आक्रोश जताया। माहौल बिगड़ता देख विधायक ने जनता से शासन स्तर पर पैरवी के लिए एक महीने का वक्त मांगा और अधिकारियों को इस अवधि में हर हाल में कार्य शुरू करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जनता से 22 जुलाई से प्रस्तावित आंदोलन को टालने की अपील की मगर जनप्रतिनिधि आंदोलन पर अड़े रहे। जिला पंचायत सदस्य संपन्न नेगी ने कहा कि क्षेत्र की जनता अब किसी खोखले आश्वासन के झांसे में नहीं आएगी। इस दौरान प्रधान दलेब सिंह सजवाण, साधना देवी, उत्तम रावत, सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण बर्वाला, गजेंद्र सिंह करासी, चंदन लाल शाह, अवतार सिंह रावत, लक्ष्मण राणा, राकेश चंद्र, योगंबर कुनियाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह नेगी आदि उपस्थित रहे।

पहाड़ में ‘सेर’ और ‘पाथा’

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। आज जब हर दुकान पर डिजिटल मशीनें लगी हैं और वजन ग्रामों में मापा जाता है, तब नई पीढ़ी शायद यह भी नहीं जानती कि कभी उत्तराखंड के पहाड़ों में सेर और पाथा ही व्यापार और जीवन का आधार हुआ करते थे। ये केवल वजन और माप की इकाइयां नहीं थीं, बल्कि पहाड़ की सामाजिक संस्कृति, विश्वास और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की पहचान थीं। पहाड़ के गांवों में धान, झंगोरा, मंडुवा, गेहूं, राजमा, गहत, भट्ट और मसूर जैसे अनाज का लेन-देन अक्सर पाथा से होता था। लकड़ी से बना एक विशेष पात्र होता था, जिसे पाथा कहा जाता था। उसमें अनाज भरकर मापा जाता था। किसी ने दो पाथा मंडुवा दिया, किसी ने पांच पाथा गेहूं उधार लिया। गांव की छोटी-बड़ी खरीद-बिक्री का यही सबसे विश्वसनीय तरीका था।

उस समय न रसीद होती थी, न बिल। केवल जुबान और भरोसा ही सबसे बड़ा दस्तावेज होता था। जब गांव से लोग कस्बों के बाजार पहुंचते थे, तब वहां सेर का बोलबाला होता था। घी, तेल, गुड़, चीनी, नमक और दालें सेर के हिसाब से खरीदी जाती थीं। दुकानदार लोहे के बाट और तराजू से सामान तौलता था। एक सेर, आधा सेर, पाव और छटांक जैसी इकाइयां हर घर की महिलाओं और किसानों की जुबान पर रहती थीं। आज की पीढ़ी किलो और ग्राम जानती है, लेकिन कभी पूरे पहाड़ की अर्थव्यवस्था सेर के इर्द-गिर्द घूमती थी।

उस दौर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं था। दुकानदार जानता था कि सामने वाला ग्राहक उसका पड़ोसी भी है। किसान जानता था कि अगली फसल तक उधार भी मिल जाएगा। यदि किसी के घर शादी होती, तो पूरा गांव अनाज पाथा-पाथा जोड़कर मदद करता। यदि किसी परिवार की फसल खराब हो जाती, तो पड़ोसी बिना हिसाब-किताब के अनाज दे देते। यही पहाड़ की असली सामाजिक पूंजी

9 अगस्त को निकलेगी स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा

अल्मोड़ा(आरएनएस)। उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन की बैठक गांधी पार्क, चौघानपाटा में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के संरक्षक किशन चंद जोशी ने की, जबकि संचालन सचिव बद्री दत्त पांडे ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष कमल पांडे ने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा में अल्मोड़ा के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों एवं उत्तराधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करते हुए अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में संरक्षक किशन चंद जोशी, कैलाश वर्मा, पुष्पा गैलाकोटी, पार्वती बिष्ट, बद्री दत्त पांडे, सरस्वती राणा, विपिन चंद जोशी आदि उपस्थित रहे।



था।

पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में नकदी का प्रचलन बहुत कम था। कई बार लोहार, बढ़ई, दर्जी और अन्य पारंपरिक कारीगरों को मजदूरी पैसे से नहीं, बल्कि अनाज में दी जाती थी। इसे स्थानीय स्तर पर अलग-

◆जब तराजू नहीं, भरोसा तौलता था सौदा, गांव की अर्थव्यवस्था का आधार था ‘पाथा’
◆न डिजिटल तराजू थे, न इलेक्ट्रॉनिक काटे, फिर भी व्यापार में थी ईमानदारी की मिसाल
◆डिजिटल जमाने ने छीन लिया पहाड़ के ‘सेर-पाथा’ वाला वह आपसी विश्वास

अलग क्षेत्रों में अलग नामों से जाना जाता था। कटाई के मौसम में पूरा गांव श्रमदान करता और बाद में पाथा के हिसाब से अनाज बांटा जाता। यह केवल लेन-देन नहीं, बल्कि सामुदायिक जीवन का हिस्सा था।

स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू हुई। सेर की जगह किलोग्राम और पाथा जैसे पारंपरिक मापों का स्थान आधुनिक मानकों ने ले लिया। बाजार आधुनिक हुए, पैकेजिंग आई, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आए और पुरानी माप-तौल की प्रणालियां इतिहास बनने लगीं। आज गांवों के बुजुर्ग ही शायद बता सकें कि एक पाथा में कितना अनाज आता था या एक सेर का वास्तविक महत्व क्या था।

वृद्ध जागेश्वर-जागेश्वर ट्रेक का आयुक्त ने किया निरीक्षण, पर्यटन सुविधाएं सुदृढ़ करने के निर्देश

अल्मोड़ा (आरएनएस)। कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को वृद्ध जागेश्वर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और इसके बाद वृद्ध जागेश्वर से जागेश्वर धाम तक पैदल ट्रेक कर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेक मार्ग की स्थिति का जायजा लिया तथा क्षेत्र में धार्मिक एवं पर्यटन विकास की संभावनाओं पर स्थानीय लोगों से चर्चा कर उनके सुझाव भी लिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने ट्रेक मार्ग के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन करते हुए क्षतिग्रस्त स्थानों की शीघ्र मरम्मत कराने तथा बरसात के दौरान फिसलन वाले हिस्सों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रेक मार्ग को सुरक्षित, सुगम और आकर्षक बनाया जाना आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक इस प्राकृतिक एवं धार्मिक धरोहर का अनुभव कर सकें। इसके बाद आयुक्त जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां

सेर और पाथा क खत्म हाने के साथ केवल माप-तौल नहीं बदली, बल्कि गांवों की जीवनशैली भी बदल गई। अब उधार मोबाइल ऐप में दर्ज होता है। रिश्ते बैंक खाते से मापे जाने लगे हैं। सामुदायिक सहयोग की जगह बाजार ने ले ली है। विश्वास की जगह लिखित अनुबंध ने ले ली है। पहाड़ की पारंपरिक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे आधुनिक बाजार में समा गई।

आज जब उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने की बात करता है, तब केवल लोकगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक वेशभूषा ही नहीं, बल्कि सेर, पाथा, नाली, मुट्ठी, छटांक जैसी पारंपरिक माप प्रणालियां भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। स्कूलों में स्थानीय इतिहास पढ़ाया जाए, संग्रहालयों में पुराने बाट, तराजू और पाथा प्रदर्शित किए जाएं, और गांवों के बुजुर्गों की स्मृतियों को दस्तावेज बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि पहाड़ की पहचान केवल हिमालय नहीं, बल्कि उसकी जीवन-पद्धति भी है।

पहाड़ का सेर केवल वजन नहीं था और पाथा केवल माप नहीं था। वे उस दौर के प्रतीक थे, जब इंसान की नीयत तराजू से भारी होती थी, भरोसा किसी रसीद का मोहताज नहीं था और गांव की समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से मापी जाती थी। शायद यही कारण है कि पुराने लोग आज भी कहते हैं पहाड़ बदल गया है, लेकिन सेर और पाथा के साथ जो अपनापन गया, उसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी।

उन्होंने भगवान जागेश्वर के दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल, यातायात प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आयुक्त ने कहा कि वृद्ध जागेश्वर से जागेश्वर धाम तक का पैदल ट्रेक धार्मिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके समुचित विकास और रखरखाव से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को ट्रेक मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, फिसलन वाले स्थानों पर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने तथा पर्यटन सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अंशुल सिंह, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, तहसीलदार ज्योति धपवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

स्वादिष्ट शाकाहारी सैंडविच के लिए आजमाएं ये 5 रेसिपी, आसान है बनाना

सैंडविच एक ऐसा व्यंजन है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। आज हम आपको कुछ ऐसे शाकाहारी सैंडविच की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खाने के स्वाद को बढ़ा देंगे और आपको नई-नई चीजें खाने का मजा देंगे। इन सैंडविच को आप नाश्ते, दोपहर के खाने या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।

पनीर टिक्का सैंडविच- पनीर टिक्का सैंडविच एक बेहतरीन विकल्प है जब आप कुछ मसालेदार और सेहतमंद खाना चाहते हैं। इसके लिए आपको पनीर के टुकड़े, दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला की जरूरत होगी। इन सभी मसालों को मिलाकर पनीर के टुकड़ों पर लगाएं और उन्हें कुछ देर के लिए रख दें। इसके बाद ब्रेड के टुकड़ों पर यह मिश्रण फैलाएं और दूसरी ब्रेड से ढक दें। फिर तवे पर सेंककर गर्मागर्म परोसें।

सब्जियों का सैंडविच- सब्जियों का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के टुकड़े लें और उन पर मलाई फैलाएं। अब इनमें कटे हुए खीरे, टमाटर, प्याज, गाजर और सलाद पत्ता डालें। आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं जैसे शिमला मिर्च, मकई आदि। इसके बाद ऊपर से दूसरी ब्रेड रखें और इसे हल्का सा सेंकें ताकि यह कुरकुरा हो जाए। आपका स्वादिष्ट सब्जियों का सैंडविच तैयार है।

आलू का चाट मसाला सैंडविच- आलू का चाट मसाला सैंडविच बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ब्रेड के टुकड़ों पर फैलाएं और ऊपर से दूसरी ब्रेड रखें। इसके बाद सैंडविच को तवे पर सेंकें जब तक कि यह सुनहरा भूरा न हो जाए। आपका स्वादिष्ट आलू का चाट मसाला सैंडविच तैयार है।

हरी चटनी वाला सैंडविच- हरी चटनी वाला सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और नमक मिलाकर चटनी तैयार करें। अब ब्रेड के टुकड़े लें और उनमें यह चटनी फैलाएं। आप इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर, प्याज आदि भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर से दूसरी ब्रेड रखें और इसे हल्का सा सेंकें ताकि यह कुरकुरा हो जाए। आपका स्वादिष्ट हरी चटनी वाला सैंडविच तैयार है।

मसालेदार टोस्ट सैंडविच- मसालेदार टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के टुकड़ों पर मक्खन लगाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डालें। आप इसमें अपनी पसंदीदा मसालेदार चीजें भी शामिल कर सकते हैं जैसे चटनी या टमाटर की चटनी आदि। इसके बाद ऊपर से दूसरी ब्रेड रखें और इसे हल्का सा सेंकें ताकि यह कुरकुरा हो जाए। आपका स्वादिष्ट मसालेदार टोस्ट सैंडविच तैयार है।

वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई गलती

वर्चुअल मीटिंग्स अब आम हो गई हैं। चाहे ऑफिस की हो या अन्य किसी तरह की, इनका सही तरीके से संचालन करना जरूरी है ताकि पेशेवर छवि बनी रहे। सही कपड़े, बैकग्राउंड, समय पर ध्यान देना और तकनीकी तैयारी रखना अहम है। इसके अलावा ध्यान रखना चाहिए कि आप बोलते समय म्यूट बटन का उपयोग करें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। इस लेख में हम आपको वर्चुअल मीटिंग्स से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं।

सही कपड़े पहनें- वर्चुअल मीटिंग्स के लिए सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। भले ही आप घर पर हों, पेशेवर दिखना अहम है। औपचारिक कपड़े पहनें ताकि आपकी पेशेवर छवि बनी रहे। अगर आप ऑफिस के लिए औपचारिक कपड़े पहनते हैं तो वही कपड़े वर्चुअल मीटिंग्स के लिए भी अच्छे रहते हैं। इससे आप खुद को अधिक पेशेवर महसूस करेंगे और आपकी छवि भी बेहतर बनेगी। उचित कपड़े आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और मीटिंग का माहौल भी गंभीर बनाते हैं।

बैकग्राउंड का ध्यान रखें- मीटिंग के दौरान बैकग्राउंड का ध्यान रखना भी जरूरी है। साफ-सुथरा और व्यवस्थित बैकग्राउंड रखें। अगर संभव हो तो दीवार पर कोई बड़ा चित्र न लगाएं क्योंकि इससे ध्यान भटक सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचें। एक साधारण और पेशेवर बैकग्राउंड सबसे अच्छा विकल्प होता है। इससे न केवल आपकी पेशेवर छवि बेहतर बनेगी, बल्कि सामने वाले को भी आपके माहौल का सही अंदाजा मिलेगा।

समय पर उपस्थित रहें- वर्चुअल मीटिंग्स में समय पर आना बहुत जरूरी है। समय पर आने से आपकी पेशेवर छवि बेहतर बनी रहती है और आप अपने साथियों का सम्मान करते हैं। अगर किसी कारणवश आप लेट हो रहे हैं तो पहले से ही संदेश कर दें कि आप थोड़ी देर से आएंगे। इससे सामने वाले को आपकी गंभीरता का पता चलेगा और वे आपकी स्थिति को समझेंगे। हमेशा समय का पालन करना एक अच्छा पेशेवर शिष्टाचार है।

म्यूट बटन का उपयोग करें- जब आप बोलते नहीं हों तो म्यूट बटन का उपयोग करना न भूलें। इससे बैकग्राउंड शोर से बचा जा सकता है और आपकी आवाज साफ-साफ सुनाई देगी। अगर आप किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए बोलने वाले हैं तो पहले म्यूट बटन अनम्यूट करें और फिर बोलें। इससे न केवल आपकी पेशेवर छवि बेहतर बनी रहती है बल्कि आप अपनी बात भी अच्छे से रख पाते हैं। सही तरीके से म्यूट बटन का उपयोग करना एक अच्छा पेशेवर शिष्टाचार है।

लॉक अप सीजन 2 में कैद होने वाली हैं टीवी की मासूम बहू शिवांगी जोशी!

टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। जल्द ही वो आने वाले रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। पर्दे पर मासूम और छुई मुई बहू का किरदार निभाने वाली शिवांगी शो में नए अवतार के नजर आने वाली हैं। इसी बीच शो के लिए एक्साइटमेंट और खुशी दिखाते हुए शिवांगी ने कई बातें शेयर की हैं।

कंटेंट के रूप में नेटफ्लिक्स के इस शो में एंट्री करने पर शिवांगी ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहूंगी और हिम्मत करके खेलूंगी। मैं बहुत सेंसिटिव और नर्वस हूं, लेकिन अब मैंने चैलेंज ले लिया है, तो इसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ूंगी। शिवांगी की ये बातें उनके फैंस को बहुत पसंद आ रही है और सभी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।

बता दें कि शिवांगी को ये रिश्ता क्या कहलाता है से नई ऊंचाई मिली और उन्हें हर घर में पहचान मिली। इसके बाद उन्हें टीवी की सबसे पसंदीदा बहू और बेटी के से एक माना जाता है। आज भी उनके शोज के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनका साथ देते हैं। अब नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो इस रियलिटी शो में दस्तक दे रही है, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करने वाले हैं। ये शो 28 जून से स्ट्रीम किया जाएगा और इसमें शिवांगी के अलावा राम कपूर जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं।

वहीं बात करें करियर की, तो शिवांगी



ने बेगूसराय सीरियल से शुरुआत की थी। वो उत्तराखंड की एक सिंपल लड़की थी, जिसे अंदाजा नहीं था कि वो यहां तक पहुंचेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनके किरदार ने सभी दर्शकों पर मानो जादू कर

दिया हो। इसके अलावा शिवांगी को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा गया, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से उन्होंने बीच के शो छोड़ दिया। अब ये शो उनके करियर को नई ऊंचाई दे सकता है।

करण जौहर ने मलायालम सिनेमा के साथ मिलकर किया फिल्म ओडियन का ऐलान



फिल्म ओडियन- द एज ऑफ इल्यूजन का आधिकारिक एलान हो चुका है। इस फिल्म का पोस्टर जारी हुआ है, जिसे करण जौहर ने शेयर किया है। यह फिल्म करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनेगी। इस तरह निर्माता का यह मलयालम सिनेमा जगत में पहला कदम है। बता दें कि ओडियन में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। उनके साथ लीड

एक्ट्रेस कौन हैं? जानिए बाकी डिटेल फिल्म ओडियन के निर्देशन की कमान राहुल सदाशिवन के कंधों पर हैं। वहीं, फिल्म में पृथ्वीराज के साथ मंजू वारियर अहम भूमिका में नजर आएंगी। करण जौहर ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। इसी के साथ उन्होंने इसे लेकर उत्साह जाहिर किया है। करण जौहर ने लिखा है, धर्मा मूवीज में हम मलयालम सिनेमा की दुनिया

में अपना पहला कदम रख रहे हैं और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे साथ इसके लिए सबसे अच्छे पार्टनर हैं।

करण जौहर ने आगे लिखा है, पृथ्वीराज, हमने साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करेंगे। हमें अपनी फिल्म ओडियन का एलान करते हुए गर्व हो रहा है, जिसे बेहद प्रतिभाशाली राहुल सदाशिवन डायरेक्ट कर रहे हैं। लोककथाओं पर आधारित डरावनी कहानियां कहने का उनका हुनर आज के सिनेमा के दौर में एक कमाल की बात है। इसे स्क्रीन पर साकार कर रही हैं शानदार मंजू वारियर और बेशक, हमारे पसंदीदा पृथ्वीराज।

फिल्म ओडियन का निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता और सुप्रिया मेनन द्वारा किया जा रहा है। यह फिल्म केरल की लोक-कथाओं के एक डरावने शेष-शिफ्टर (रूप बदलने वाले जीव) के बारे में है। उसका गुस्सा एक ताकतवर और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार पर टूट पड़ता है, जिससे सच और भ्रम के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जिसमें पौराणिक कथाओं, खतरे और मनोवैज्ञानिक गहराई का संगम देखने को मिलता है। यह राहुल सदाशिवन का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है।

जंगली सुअरों के फसलों को बचाने के लिए डीएफओ से लगाई गुहार

विकासनगर(आरएनएस)। कालसी भेड़ बकरी किसान उत्पादक संगठन ने डीएफओ चकराता को ज्ञापन प्रेषित कर कालसी ब्लाक के कई गांवो में जंगली सुअरों से फसलों के नुकसान को बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपाय कराए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कालसी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम मटियावा, दोहा, झुसोऊ, बड़ोडा, दोऊ समेत आसपास के गांवो में जंगली सुअरों द्वारा पिछले कुछ समय से उनकी मक्का, राजमा, खीरा, गोभी, मटर, टमाटर आदि की फसलों को भारी क्षति पहुंचाई जा रही है। जिसके चलते किसानों को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है। बताया कि पूरा दिन ग्रामीण अपने खेतों की देखभाल करते हैं लेकिन रात के समय सुअर खेतों में घुसकर उनकी फसलों को तहस नहस कर देते हैं।विभाग को गत वर्ष भी इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस कारण अनेक किसानों द्वारा इस बार फसल की बुआई नहीं की गई। बताया कि इस नुकसान के चलते लोग परेशान हैं और खेती छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। कहा कि यदि गांव में रहने वाले ग्रामीण किसानी छोड़ देंगे तो यह पलायन का बड़ा कारण बनेगा।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 200 मरीजों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

अल्मोड़ा(आरएनएस)। नगर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में करीब 2०० मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। मेडिकल हॉल एवं इसके सहयोगी प्रतिष्ठान लक्ष्मी मेडिकल हॉल, चौक बाजार के संयोजन में आयोजित शिविर में पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हल्द्वानी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. करण छाबड़ा और डॉ. सुमित खत्री ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श दिया। शिविर में पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, फैटी लिवर, पीलिया, अल्सर, कब्ज सहित पाचन संबंधी रोगों से पीड़ित मरीजों की जांच की गई। इसके अलावा अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया, फेफड़ों के संक्रमण, सांस फूलने और लगातार खांसी जैसी समस्याओं से ग्रसित मरीजों का भी परीक्षण किया गया।

शिविर में ब्लड प्रेशर और रक्त जांच की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। शिविर के शुभारंभ पर मेडिकल हॉल के संचालक राघव पंत ने हल्द्वानी से पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्वागत किया। आयोजन की सफलता को देखते हुए भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की घोषणा की गई। शिविर के सफल आयोजन में कुमाऊं के पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉ. जे.सी. दुर्गापाल, समाजसेवी किशन गुरूरानी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. हर्षवर्धन पंत, तकनीशियन जगदीश बिष्ट तथा भगवान दत्त साह सहित अन्य लोगों का सहयोग रहा।

सू- दोकू क्र.095								
	7			4		3		
2			3			9		4
	6			2				
3		1			7		4	
	2			1			6	
8			9		4			1
		2		3		7		
1			7		2	4		3
	5	3		8			7	2

नियम 1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है। 2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है। 3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।	सू-दोकू क्र.94का हल								
	9	2	8	3	1	5	7	4	6
	4	1	6	8	9	7	2	5	3
	7	3	5	4	6	2	8	1	9
	2	7	3	9	8	1	4	6	5
	5	4	1	6	7	3	9	2	8
	6	8	9	2	5	4	1	3	7
	3	6	2	7	4	9	5	8	1
8	5	7	1	2	6	3	9	4	
1	9	4	5	3	8	6	7	2	

सात मोड़ पर ‘सियासत’ सात सौ पर ‘सन्नाह’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति का भी अपना एक भूगोल है। यह भूगोल नक्शे से नहीं, बल्कि सड़कों से तय होता है। जहां तक एसी वाली गाड़ियां आराम से पहुंच जाती हैं, वहां धरना भी होता है, प्रदर्शन भी होता है, कैमरे भी पहुंचते हैं और नेताओं के बयान भी। लेकिन जहां पहुंचने के लिए सात सौ मोड़ पार करने पड़ें, जहां सड़क आज भी अधूरी हो, जहां एंबुलेंस नहीं पहुंचती और मरीजों को चारपाई पर ढोना पड़ता हो, वहां न कोई आंदोलन दिखाई देता है और न कोई राजनीतिक संवेदना।

प्रदेश बनने के बाद से लेकर आज तक पुरोला की जनता ने हर दल और हर चेहरे पर भरोसा किया। कभी कांग्रेस को मौका दिया, कभी भाजपा को। मालामाल नेताओं को जनता ने वोट देकर विधानसभा और संसद तक पहुंचाया। किसी को विधायक बनाया, किसी को सांसद। चुनाव दर चुनाव उम्मीद यही रही कि अब शायद गांव तक सड़क पहुंचेगी, अस्पताल बेहतर होंगे, पलायन रुकेगा और पहाड़ की जिंदगी आसान होगी। नेता बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, चुनावी नारे बदलते रहे, मगर पुरोला के कई गांवों की तस्वीर नहीं बदली। जिन नेताओं को जनता ने सिर आंखों पर बैठाया, वह राजधानी की राजनीति में रम गए। उनके परिवार शहरों में बस गए। बच्चों की पढ़ाई महानगरों में हुई, इलाज बड़े अस्पतालों में हुआ और सुविधाओं से भरपूर जीवन उनकी नई पहचान बन गया। दूसरी ओर, जिन लोगों के वोट से यह राजनीतिक सफ़र तय हुआ, वह आज भी सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

हाल के दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में सड़क और प्रदर्शन दोनों चर्चा का विषय बने हैं। लेकिन एक सवाल बार-बार उठता है क्या आंदोलन भी अब सड़क देखकर तय होंगे? जहां तक आरामदायक सड़क है, वहां प्रदर्शन करना आसान है। मीडिया पहुंच जाएगा, कैमरे लग जाएंगे, सोशल

मीडिया पर वीडियो बन जाएंगे और कुछ घंटे बाद सब अपने-अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन प्रदेश के पुरोला जैसे इलाकों में, जहां गांव तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मोड़ और कई किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ता है, वहां कौन जाएगा? क्या किसी बड़े नेता ने कभी दोणी जैसे दूरस्थ गांवों तक जाकर वहां की वास्तविक स्थिति देखने की कोशिश की?

बता दें कि पुरोला क्षेत्र का दोणी गांव केवल एक गांव नहीं, बल्कि उस विकास

◆**जहाँ तक आराम से दौड़ सकती हैं एसी गाड़ियाँ, कैमरे व बयानबाजी का पारखंड सिर्फ वहीं तक**
◆**जनता ने नेताओं को फर्श से अर्श पर पहुँचाया, बदले में मिलीं सिर्फ अधूरी सड़कें**
◆**उतराखंड का हाल, जहां सड़क नहीं पहुंची, वहां राजनीति भी नहीं पहुंचती**

माडल पर सवाल है, जिसमें राजधानी चमकती है लेकिन सीमांत अंधेरे में रह जाता है। बताया जाता है कि आज भी गांव के लोग सड़क के अभाव में गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हैं। बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना किसी परीक्षा से कम नहीं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की तकलीफें चुनावी भाषणों का हिस्सा तो बनती हैं, लेकिन समाधान का नहीं। जब कोई मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता, तब वह केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की असफलता होती है।

आज का दौर सोशल मीडिया का है। नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं। कहीं पेड़ के चारों ओर घूमकर रील बनाई जाती है, कहीं विकास के दावे कैमरे के सामने दोहराए जाते हैं। लेकिन पहाड़ की असली रील कोई कैमरा रिकार्ड नहीं करता। वह रील उस मरीज की है जिसे चार लोग कंधे पर उठाकर सड़क तक ला रहे हैं। वह रील उस बुजुर्ग की है जो इलाज के लिए घंटों सफर करता है। वह रील उस छात्र की है जिसे पढ़ाई के लिए गांव छोड़ना पड़ता है। वह रील उस मां की है जो बारिश में

फिसलते रास्तों पर राशन ढोती है। यह रील वायरल नहीं होती, क्योंकि यहां कैमरे कम और तकलीफें ज्यादा हैं।

कल्पना कीजिए, यदि दोणी गांव तक अच्छी सड़क होती, यदि वहां एसी कारें पहुंच सकतीं, यदि राजनीतिक काफिले आसानी से पहुंच जाते, तो शायद वहां भी मंच सजता, नारे लगते, फोटो खिंचती और सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़े-बड़े दावे किए जाते। शायद किसी राष्ट्रीय नेता का काफिला रोकने की घोषणा भी होती। शायद संसद में आवाज उठाने की चेतावनी भी दी जाती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह गांव सात मोड़ों पर नहीं, सात सौ मोड़ों के पार है। वहां पहुंचना कठिन है, इसलिए वहां की पीड़ा भी राजनीति की प्राथमिकता नहीं बन पाती।

उत्तराखंड सरकार लगातार विकसित उत्तराखंड, अंतिम छोर तक विकास और सड़क हर गांव तक जैसे दावे करती रही है। कई सड़क परियोजनाओं की घोषणाएं भी हुई हैं। लेकिन यदि राज्य बनने के ढाई दशक बाद भी सीमांत गांव सड़क के लिए तरस रहे हैं, तो सवाल केवल किसी एक गांव का नहीं, बल्कि विकास की पूरी अवधारणा का है। क्या विकास केवल चारधाम मार्ग तक सीमित रहेगा? क्या राजधानी और पर्यटन क्षेत्रों की चमक ही विकास का पैमाना होगी?क्या सीमांत क्षेत्रों का नागरिक केवल चुनाव के समय याद किया जाएगा?

प्रदेश में पुरोला, दोणी और ऐसे ही अनेक गांव अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनकी सड़क कब बनेगी, एंबुलेंस कब पहुंचेगी, अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता कब आसान होगा और उनके बच्चों को भी वही सुविधाएं कब मिलेंगी जो राजधानी के लोगों को सहज उपलब्ध हैं। क्योंकि लोकतंत्र की असली परीक्षा राजधानी की चौड़ी सड़कों पर नहीं, बल्कि उन सात सौ मोड़ों के पार होती है जहां आज भी विकास पहुंचने का इंतजार कर रहा है।

धरासू-जोगत मोटर मार्ग पर तुल्याड़ा भूस्खलन जोन से खतरा

उत्तरकाशी(आरएनएस)। धरासू-जोगत मोटर मार्ग पर तुल्याड़ा गांव के समीप पिराड़ा क्षेत्र में वर्षों से सक्रिय भूस्खलन एवं डेंजर जोन ग्रामीणों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। हर दिन लोग वहां पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं लेकिन कई बार शासन-प्रशासन से पत्राचार के बाद भी वहां पर मरम्मतीकरण और सुरक्षात्मक कार्य नहीं हो पा रहा है।

कनिष्ठ प्रमुख भानुप्रिया थपलियाल, हरीश थपलियाल, अनिल पंवार, विजयपाल परमार, राहुल रजवार, शुभम रावत का कहना है कि वर्षों से शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तुल्याड़ा के समीप मोटर पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुल के निर्माण से भूस्खलन जोन से भी सुरक्षा हो जाएगी। आजकल बरसात में भूस्खलन और पत्थर गिरने से लोगों में हर समय दुर्घटना का डर बना है।

भानुप्रिया थपलियाल ने कहा कि अगर जल्द ही तुल्याड़ा में मोटर पुल निर्माण की स्वीकृति और कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। गत सप्ताह वहां पर बोल्टर आने के कारण एक व्यक्ति खाई में गिरने से गंभीर घायल हो गया था।

पर्यटक स्थल की घोषणा से बौख टिब्बा को मिलेगी नई पहचान

उत्तरकाशी(आरएनएस)। समुद्र तल से तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बौख टिब्बा को अब नई पहचान मिलने की उम्मीद जगी है।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बौखटिब्बा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी है। बौख टिब्बा के नाम को पर्यटन के मानचित्र पर दर्ज करने और बौख टिब्बा को जोड़ने वाले ट्रैक को सालों

से विकसित करने की मांग उठ रही थी।सिलक्यारा टनल हादसे के दौरान इस स्थान की अंतरराष्ट्रीय स्तर तक चर्चा हुई थी। बौख टिब्बा ट्रेकिंग और धार्मिक पर्यटन की बेहतरीन संभावनाएं है। बाबा बौखनाग देव समिति के अनुरोध पर पर्यटन मंत्री महाराज ने बौख टिब्बा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के व्यक्तिगत निमंत्रण पर बाबा बौखनाग की देव डोली 17 जुलाई को उनके

निजी आवास देहरादून पहुंची थी। वहां देव डोली के दर्शन करने पहुंचे प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देव समिति के ज्ञापन पर बौख टिब्बा को पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा की है। पर्यटन मानचित्र पर नाम न होने से बौखटिब्बा पर्यटकों की दृष्टि से ओझल था जिसे अब नई पहचान मिलने की उम्मीद जगी है। बाबा बौखनाग के देव माली संजय डिमरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पर्यटन मंत्री की घोषणा को साझा किया है।



कांवड़ यात्रा: एसपी देहात की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

हमारे संवाददाता हरिद्वार। नगर निगम रुड़की के हॉल में आज आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्र के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसपी सुयाल सहित अन्य पुलिस ऑफिसर्स द्वारा स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स से वार्ता करते हुए उन्हें आगामी कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन के लिए अब तक बनाई गई योजना की जानकारी देते हुए यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, शिवभक्तों को कांवड़ पटरी में भेजने आदि के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए पूर्व के वर्षों की भांति सहयोग की अपेक्षा की गई।

विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार संघ ने किया सचिवालय कूच

संवाददाता देहरादून। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया। जिनको सचिवालय से पहले ही बैरकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। आज यहां बेरोजगार संघ के पदाधिकारी व सदस्य परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने सचिवालय के लिए कूच किया। जब वह सचिवालय के समक्ष पहुंचे तो पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ गये। उन्होंने कहा कि वह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन उनकी मांगों के प्रति गम्भीर नहीं है तथा उनकी मांगों पर किसी प्रकार का सकारात्मक कार्यवाही अभी तक नहीं हो पायी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र रूप धारण किया जायेगा।

एक हजार की ईनामी सहित दो वारंटी गिरफ्तार

संवाददाता टिहरी। पुलिस ने एक हजार के ईनामी सहित दो वारंटियों को गिरफ्तार कर उनको न्यायालय में पेश किया। आज यहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में जनपद में ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार एवं वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में टिहरी पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली चंबा एवं थाना घनसाली पुलिस ने अलग-अलग मामलों में दो गैर-जमानती वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल एवं क्षेत्राधिकारी चंबा के पर्यवेक्षण में कोतवाली चंबा पुलिस ने अपर सिविल जज, टिहरी गढ़वाल द्वारा जारी स्थायी गैर-जमानती वारंट का सफलतापूर्वक तामील करते हुए एक हजार के इनामी एवं स्थायी गैर-जमानती वारंटी हिमानन्द पंत पुत्र राखी राम, निवासी ग्राम कोटद्वारा, पोस्ट टिंगरी, थाना चंबा, जनपद टिहरी गढ़वाल को रानीचौरी-नकोट क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

जेन जेड की ‘आवाज’ पर राष्ट्रीय बहस..

◀ पृष्ठ 2 का शेष

को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार का यह भी आरोप है कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों के आंदोलन को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन को जिस तरह विपक्ष और सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों का समर्थन मिला है, उससे सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष इस मुद्दे को कानून-व्यवस्था और राजनीतिक उकसावे के नजरिए से देख रहा है। ऐसे में संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे पर तीखी टकराहट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल छात्र संगठन अपने आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हैं और सरकार की ओर से भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात दोहराई जा रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता निकलता है या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेता है। यह है पूरा मामला : देशभर से छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और हिरासत की घटनाएं सामने आईं। कांसेराई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़, जबकि सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। आंदोलन अभी जारी है और इस पर देशभर की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।

देवभूमि में ‘आस्था’ पर ‘सियासत’

कार्यालय संवाददाता देहरादून। बदरीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला अब केवल जांच का विषय नहीं रहा, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी हथियार बनता जा रहा है। राजधानी देहरादून में महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित भाजपा और कांग्रेस मुख्यालयों में हुई दो अलग-अलग पत्रकार वार्ताओं ने यह साफ कर दिया कि देवभूमि की आस्था अब राजनीतिक अखाड़े के केंद्र में आ चुकी है। एक ओर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी मीडिया के सामने आए और आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि जांच चल रही है और सच सामने आएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार और बीकेटीसी पर तीखा हमला बोलते हुए पूरे प्रकरण को प्रशासनिक विफलता और जवाबदेही के संकट का प्रतीक बताया।

भाजपा की प्रेस वार्ता का मूल संदेश था कि सरकार ने मामले को दबाने के बजाय जांच कराई, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हुई और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी ने विपक्ष पर आस्था के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। इसके कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने उसी मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। गणेश गोदियाल ने सवाल उठाया कि यदि

व्यवस्थाएं इतनी मजबूत थीं तो आखिर चढ़ावे की चोरी हुई कैसे? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर देने से जवाबदेही पूरी हो जाती है, या शीर्ष स्तर पर भी नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

◆राजधानी में एक ही दिन में दो मुख्यालयों में घंटों चला ‘सियासी महाभारत’
◆भाजपा ने कहा-सत्य सामने आएगा, कांग्रेस बोली चोरी नहीं, सिस्टम की मिलीभगत
◆बदरीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित चोरी के मुद्दे पर आमने-सामने आए भाजपा-कांग्रेस

बदरीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे में कथित चोरी की घटना स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय है। लेकिन जिस तरह दोनों प्रमुख दल इसे अपने-अपने राजनीतिक नैरेटिव के अनुरूप पेश कर रहे हैं, उससे यह मामला अब धार्मिक भावना से आगे बढ़कर चुनावी विमर्श का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की पारदर्शिता बनाम विपक्ष की राजनीति के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, जबकि कांग्रेस इसे भ्रष्ट

लक्ष्य, समय-सीमा और जवाबदेही के बिना अधूरा रहेगा मास्टर प्लान: साइकिलिंग क्लब

संवाददाता देहरादून। देहरादून साइकिलिंग क्लब ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) से मांग की है कि देहरादून मास्टर प्लान-2041 को अंतिम रूप देने से पहले जनसुनवाई में प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों को गंभीरता से शामिल किया जाए। क्लब का कहना है कि मास्टर प्लान केवल भूमि उपयोग का दस्तावेज नहीं, बल्कि शहर के भविष्य का रोडमैप होना चाहिए।

क्लब के अध्यक्ष हरिसिमरन सिंह ने कहा कि मास्टर प्लान में सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर परिवहन व्यवस्था की बात तो की गई है, लेकिन

इसमें समयबद्ध लक्ष्य, मापनीय परिणाम और जवाबदेही का अभाव है। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्ष 2041 तक 30-40 प्रतिशत यात्राएं सार्वजनिक परिवहन तथा 20-25 प्रतिशत यात्राएं साइकिल से कराने जैसे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। क्लब ने कहा कि वर्तमान मसौदे में सड़क, पेयजल, सीवरेज, पार्किंग, वायु गुणवत्ता, भूजल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी मूलभूत चुनौतियों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही सुरक्षित साइकिल ट्रैक, साइकिल हाईवे, सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम, बेहतर बस सेवा, समर्पित बस लेन, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन और वैज्ञानिक पार्किंग

व्यवस्था और जवाबदेही के अभाव का प्रतीक बनाकर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों की रणनीति स्पष्ट दिखने लगी है। कांग्रेस सरकार की साख पर सवाल खड़े करने के लिए बदरीनाथ प्रकरण को लगातार उठाना चाहती है। वहीं भाजपा यह संदेश देने में जुटी है कि उसने मामले में कार्रवाई कर यह साबित किया है कि भ्रष्टाचार पर उसकी नीति जीरो टालरेंस की है। यानी यह लड़ाई केवल एक चोरी की नहीं, बल्कि विश्वास बनाम जवाबदेही की राजनीतिक लड़ाई बनती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या बदरीनाथ धाम जैसे पवित्र स्थल से जुड़ा मामला निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तक सीमित रहेगा, या फिर 2027 के चुनाव तक यह भाजपा और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा? फिलहाल तस्वीर यही है कि एक मुख्यालय से सफाई दी जा रही है, दूसरे मुख्यालय से सवाल दागे जा रहे हैं। बीच में खड़ी है देवभूमि की जनता, जो यह जानना चाहती है कि आखिर चढ़ावे की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, जिम्मेदार कौन है, और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे।

नीति को भी मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। क्लब ने किराया देवता, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), शहरी वन, जल संरक्षण और हरित क्षेत्रों के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। क्लब का कहना है कि यदि स्वास्थ्य, पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाए तो देहरादून देश की पहली साइकिलिंग-फ्रेंडली पर्वतीय राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्लब ने एमडीडीए और राज्य सरकार से जनसुनवाई में मिले सुझावों को शामिल कर मास्टर प्लान-2041 को जन-केंद्रित, पर्यावरण-अनुकूल और समयबद्ध बनाने की अपील की।

दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमला: लालचंद शर्मा

हमारे संवाददाता देहरादून। परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही धांधली और पेपर लीक की घटनाओं से आहत युवाओं का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने केंद्र सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा।

लालचंद शर्मा ने कहा कि देश का युवा मेहनत और ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन बार-बार पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के कारण उसका भविष्य बर्बाद हो रहा

है। जब युवा अपनी आवाज उठाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन पर लाठियां बरसाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता और तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। केंद्र सरकार को युवाओं की आवाज दबाने के बजाय परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व महानगर अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षाओं में धांधली की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि

उत्तराखंड में भी युवा लगातार भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक से परेशान रहे हैं। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने और भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। लालचंद शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। उन्होंने मांग की कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ कांग्रेस बर्बाद नहीं करेगी।

यूकेडी में 'अंदरूनी' हलचल

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब अनुशासन का डंडा केवल राष्ट्रीय दलों तक सीमित नहीं रह गया है। भाजपा और कांग्रेस में लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बाद अब क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल भी उसी राह पर चलता दिखाई दे रहा है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता आशुतोष नेगी को केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाकर साफ संकेत दे दिया है कि संगठन के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी या समानांतर राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब प्रदेश की राजनीति धीरे-धीरे 2027 विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है और हर दल अपने संगठन को मजबूत व अनुशासित दिखाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यूकेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टी, जो वर्षों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इस समय अनुशासनात्मक कार्रवाई का जोखिम उठा सकती है?

पिछले कुछ महीनों में भाजपा ने कई नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए और संगठन विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई की। कांग्रेस ने भी कई नेताओं पर अनुशासनात्मक कदम उठाए। अब यूकेडी में आशुतोष नेगी को केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद यह संदेश गया है

कि क्षेत्रीय दल भी अब अंदरूनी असहमति को खुलकर स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि संगठन के भीतर अनुशासन स्थापित करने की कोशिश है। यूकेडी लंबे समय से गुटबाजी, नेतृत्व विवाद और लगातार कमजोर होते जनाधार से जूझती रही है। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता पर कार्रवाई दो तरह के संदेश देती है। एक

◆**चुनाव से पहले राष्ट्रीय दलों की राह पर उत्तराखंड क्रांति दल**
◆**आशुतोष नेगी पर कार्रवाई से क्षेत्रीय राजनीति में खलबली**
◆**2027 चुनाव से पहले यूकेडी में आपरेशन क्लीन या कुछ ओर**

ओर नेतृत्व अपनी पकड़ मजबूत दिखाता है, वहीं दूसरी ओर असंतुष्ट नेताओं का नया खेमा भी तैयार हो सकता है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि पार्टी इस विवाद को समय रहते नहीं संभालती, तो चुनाव से पहले इसका नुकसान संगठनात्मक स्तर पर उठाना पड़ सकता है। उत्तराखंड में यूकेडी कभी राज्य आंदोलन की सबसे मजबूत राजनीतिक आवाज हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ पार्टी का जनाधार लगातार सिमटता गया। आज स्थिति यह है कि भाजपा और

कांग्रेस के बीच क्षेत्रीय राजनीति के लिए जगह बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में यदि पार्टी के भीतर ही असंतोष खुलकर सामने आने लगे, तो उसका असर चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूकेडी नेतृत्व अब चुनाव से पहले संगठन को एकजुट और नियंत्रित रखना चाहता है। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि व्यक्तिगत बयान या अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल इस कार्रवाई को यूकेडी की आंतरिक कमजोरी और नेतृत्व संकट के रूप में भी पेश कर सकते हैं। आशुतोष नेगी को पद से हटाने का फैसला केवल एक संगठनात्मक आदेश नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की राजनीति में बदलते राजनीतिक व्यवहार का संकेत भी है। अब चाहे राष्ट्रीय दल हों या क्षेत्रीय, हर पार्टी चुनाव से पहले अनुशासन पहले, असहमति बाद में की नीति पर चलती नजर आ रही है। लेकिन राजनीति का इतिहास बताता है कि अनुशासन संगठन को मजबूत भी करता है और कभी-कभी असंतोष की नई चिंगारी भी जगा देता है। यूकेडी के लिए यह फैसला किस दिशा में जाएगा, इसका जवाब आने वाले महीनों में पार्टी की एकजुटता और 2027 की चुनावी तैयारियां देंगी।

हाईकोर्ट ने दिल्ली मार्च में जा रहे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी अध्यक्ष को रोकने पर पुलिस को लगाई फटकार

संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिल्ली में आयोजित सीजेपी के संसद मार्च में शामिल होने जा रहे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपप) के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पुलिस से पूछा कि यदि धारा 144 का उल्लंघन होना था तो वह दिल्ली में होता, ऐसे में उत्तराखंड पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार किस आधार पर मिला। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कार्रवाई गुंडागर्दी जैसी प्रतीत होती है। अदालत ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा, आप इस देश में क्या कर रहे हैं? क्या सरकार की छवि बचाने के लिए हैं या लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए? पुलिस का यह आचरण पूरी तरह हास्यास्पद है। यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि 20 जुलाई को प्रभात ध्यानी को नई दिल्ली में आयोजित संसद मार्च में शामिल होने के लिए जाते समय उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और एक अन्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई की वैधानिकता और अधिकार क्षेत्र को लेकर कई तीखे सवाल उठाए।



सीएम धामी ने किया 235 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास

संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत लगभग 235 करोड़ रुपये की विभिन्न आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का किया भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत लगभग 235 करोड़ रुपये की विभिन्न आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का किया भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। उत्तराखण्ड निवेश एवं आधारीक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) द्वारा संचालित इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरिद्वार में आधुनिक, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सुविधाओं का विकास करना है। होटल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 43.25 करोड़ रुपये की लागत से प्रशासनिक मार्ग परियोजना का भूमि पूजन किया। साथ ही 66.76 करोड़ रुपये की लागत से हर की पैड़ी एवं सुभाष घाट के पुनरुद्धार, 66.34 करोड़ रुपये की लागत से हर की पैड़ी के उत्तर क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना विकास तथा 58.84 करोड़ रुपये की लागत से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र के पुनरुद्धार कार्यों का शिलान्यास किया।

यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता: गढ़वाल आयुक्त

संवाददाता
देहरादून। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज यहां यात्रा मार्गों पर आवश्यक समीक्षा के उपरांत चारधाम यात्रा, जिसे 20 जुलाई 2026 को एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था, पुनः सुचारु रूप से संचालित कर दी गई है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जनपदों के जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर यात्रा का संचालन किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की निरंतर निगरानी की जा रही है तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के



दौरान यदि किसी स्थान पर भारी वर्षा, भूस्खलन अथवा अन्य कारणों से यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित होता है, तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों अथवा होल्डिंग एरिया में ही रुकें तथा प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि यात्रियों

की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभागों को मौसम की स्थिति तथा यात्रा मार्गों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा सके। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व मौसम की ताजा जानकारी प्राप्त करें तथा केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 मजदूरों की मौत, कई लापता

संवाददाता
नई दिल्ली। सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में बड़ा हादसा हो गया। सुरंग के अंदर मिथेन गैस में विस्फोट होने के बाद भूस्खलन हुआ, जिससे सुरंग का एक हिस्सा बंद हो गया और 27 से ज्यादा मजदूर अंदर फंस गए। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक, सुरंग के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर तक मिथेन गैस जमा हो गई थी। गैस को बाहर निकालने की कोशिश के दौरान विस्फोट



हुआ, जिसके बाद सुरंग का रास्ता मलबे से बंद हो गया। हादसे के बाद कुछ मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कई मजदूर अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ,

जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों मौके पर पहुंचीं। हालांकि, सुरंग के अंदर जहरीली गैस, ऑक्सीजन की कमी और बेहद कम दृश्यता के कारण बचाव अभियान में भारी मुश्किलें आ रही हैं। शुरुआती रेस्क्यू के दौरान फायर ब्रिगेड

के कई जवानों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद अभियान रोकना पड़ा। हालांकि फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव अभियान को तेज करने के लिए पश्चिम बंगाल से विशेष गैस-प्रोटेक्शन उपकरणों से लैस टीम भी बुलाई गई है। एंबुलेंस मौके पर तैनात हैं और गैस मास्क व सुरक्षा उपकरणों के साथ रेस्क्यू टीमें लगातार मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक, सुरंग में जहरीली मिथेन गैस, संकरा रास्ता और कम दृश्यता बचाव अभियान को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। फिलहाल सभी एजेंसियां युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटेर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटेर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।